

राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 23 लाख से अधिक कामगारों/श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया गया है : मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार सभी कामगारों/श्रमिकों को सुरक्षित व सम्मानजनक ढंग से वापस लाएगी

कामगारों/श्रमिकों के सेवायोजन एवं रोजगार के लिए प्रदेश सरकार एक आयोग का गठन करेगी

सभी विभाग प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रु० के आर्थिक पैकेज के तहत कार्य योजना बनाकर अविलम्ब लागू करें

प्रत्येक कामगार/श्रमिक को राशन किट/राशन कार्ड तथा होम क्वारंटीन के दौरान 1,000 रु० का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए

लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, इसके लिए पी०आर०वी० 112 से पेट्रोलिंग के साथ-साथ अधिकारीगण भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग तेज करें

सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों को क्वारंटीन सेन्टर, कम्युनिटी किचन, कोविड अस्पतालों इत्यादि का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश

प्रदेश के एम०एस०एम०ई० सेक्टर में रोजगार की असीम सम्भावनाएं मौजूद

प्रदेश में माइनिंग सामग्री जैसे बालू, गिट्टी, मौरंग इत्यादि की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

यह सभी सामग्री उचित और निर्धारित मूल्य पर ही जनता को मिले

कोरोना संक्रमण के कारण ईद पर कोई समारोह आयोजित न किया जाए, सभी मुस्लिम भाई स्वयं को इस संक्रमण से बचाते हुए घर पर ही ईद मनाएं : मुख्यमंत्री

लखनऊ : 24 मई, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख कामगारों/श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया गया है। राज्य सरकार इन सभी की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य वापस आने वाले सभी श्रमिकों व कामगारों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेन्टर अथवा होम क्वारंटीन पर भेजा जाए। होम

क्वारेन्टीन जाने वाले श्रमिकों/कामगारों को खाद्यान्न किट अवश्य दी जाए तथा इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं। साथ ही, इन्हें होम क्वारेन्टीन के दौरान 1,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री जी आज अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कामगारों/श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके तहत इन कामगारों/श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कामगारों/श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्योरा इकट्ठा किया जाए। तत्पश्चात उन्हें रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाए। कृषि विभाग तथा दुग्ध समितियों इत्यादि में इन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कामगारों/श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमे का लाभ देने की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे इनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा। ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे कामगारों/श्रमिकों को जॉब सिक्योरिटी मिल सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने इस पैकेज में किराए का मकान देने की योजना को भी शामिल करने के लिए कहा। आवास योजना के तहत किराए पर मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जरूरतमंदों को कम किराए पर आवास उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पी0एम0 आर्थिक पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्य योजना बना ली जाए।

मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस व प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग करें और कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने दें। पी0आर0वी0 112 की वैन लगातार पेट्रोलिंग करती रहें। उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों

को क्वारंटीन सेन्टर, कम्युनिटी किचन, कोविड अस्पतालों इत्यादि का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्थलों, मार्गों/एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले कामगारों/श्रमिकों, जरूरतमंदों इत्यादि को फूड पैकेट बाटे जाएं, ताकि कोई भी भूखा न रहे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की निगरानी के लिए गठित की गई निगरानी समितियां पूरी सक्रियता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। चिन्हित कन्टेनमेन्ट जोनों में डोर स्टेप डिलीवरी प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में हो। उन्होंने टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर बुन्देलखण्ड में पेयजल की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहां किसी भी हाल में पानी की कमी न होने पाए।

मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव राजस्व को निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि विशेष सचिव स्तर के जो अधिकारी शासन द्वारा जनपदों में भेजे गए हैं, वे नियमित रूप से कम्युनिटी किचन और क्वारंटीन सेन्टर का निरीक्षण करें। साथ ही, मजदूरों को राशन किट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए और इनके बैंक खाते खोलने की भी व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन आपस में अच्छा समन्वय स्थापित करें, तभी लॉकडाउन सफल हो सकेगा। उन्होंने मास्क न पहनने वालों का चालान करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आजीविका मिशन के तहत निर्मित मास्क उपलब्ध कराए जाएं। मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में भी रोजगार की असीम सम्भावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना से जंग के मद्देनजर प्रदेश में मानक के अनुरूप पी0पी0ई0 किट्स, एन-95 मास्क, थ्री लेयर मास्क व अन्य उपकरणों का निर्माण एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी अस्पतालों में मौजूद वेण्टीलेटर फंक्शनल होने चाहिए। सभी जगह एनस्थीसियोजलॉजिस्ट की नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 'ट्रू नेट' मशीनें मगांकर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता 10 हजार तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी क्वारंटीन सेन्टरों पर पल्स ऑक्सीमीटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल ईद है। इसके मद्देनजर पुलिस व प्रशासन संयुक्तरूप से पेट्रोलिंग करें। कोरोना संक्रमण के कारण ईद पर कोई समारोह आयोजित न किया जाए। सभी मुस्लिम भाई स्वयं को इस संक्रमण से बचाते हुए घर पर ही ईद मनाएं।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में माइनिंग सामग्री जैसे बालू, गिट्टी, मौरंग इत्यादि की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में इन खनिजों की कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि यह सभी सामग्री उचित और निर्धारित मूल्य पर ही जनता को मिले।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री श्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री श्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव श्री आर०के० तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी० अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस०पी० गोयल तथा श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम०एस०एम०ई० श्री नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।